

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 13 अप्रैल, 2011
विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या:-209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों में कुल धनराशि ₹ 8,88,62,000/- (रुपये आठ करोड़ अठासी लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह में 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।
6. इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फिल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2- उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-18 के लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता आयोजनेत्तर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण की निम्नलिखित सुसंगत इकाईयो के नामें डाला जायेगा:-

मानक मद व मद का नाम	धनराशि (हजार ₹0 में)
01- वेतन	51000
03- महंगाई भत्ता	30600
04- यात्रा व्यय	800
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	60
06- अन्य भत्ते	5610
08- कार्यालय व्यय	60
09- विद्युत देय	150
10- जलकर/जलप्रभार	5
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	60
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6
13- टेलीफोन पर व्यय	60
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	170
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	70
17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	75
18- प्रकाशन	6
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	6
27- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	70
29- अनुरक्षण	6
42- अन्य व्यय	12
45- अवकाश यात्रा व्यय	6
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	12
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	18
योग	88862

(रू0 आठ करोड अठासी लाख बासठ हजार मात्र)

3:- ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या:-209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या:-593(1)/XIV-1/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-4/वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. प्रभारी मिडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,


(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उपसचिव।